भाकृअनुप–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान
जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002
(उत्तर प्रदेश)
An ISO 9001:2015 Certified

(O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : http://atarik.res.in
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

दि. 16–06–2020

आर्या परियोजना की समीक्षा कार्यशाला

आज दि. 16 जून 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा देश के 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संचालित आर्या परियोजना का आनलाइन समीक्षा कार्यशाला का अयोजन किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक, भा.कृ.अनुप., नई दिल्ली, डा. त्रिलोचन महापात्र, उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) डा. ए.के. सिंह, डा. जी. त्रिवेदी, पूर्व कुलपति राँची कृषि विश्वविद्यालय, राँची, डा. नारायणगौड़ा, पूर्व कुलपति, बंगलौर, अटारी जोन–3 कानपुर के निदेशक डा. अतर सिंह सहित सभी जोन के निदेशक, एवं उत्तर प्रदेश के परियोजना से जुड़े 10 कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एवं देश के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।

समीक्षा बैठक के उद्घाटन अवसर पर महानिदेशक भा.कृ.अनुप., नई दिल्ली ने परियोजना के उद्देश्यों तथा ग्रामीण युवाओं को कृषि सम्बंधी व्यवसायों से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलयान रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे कैसे जोड़ा जाय जिससे कम समय में वह आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बन सकें। उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्रों से अपेक्षा की कि वह इस परियोजना में गम्भीरता से काम करें जिससे ग्रामीण युवकों को कृषि व्यवसाय से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इस दिशा में उड़ीसा राज्य ने 5 प्रतिशत युवाओं को इस परियोजना से जोड़कर लाभान्वित करने का उल्लेखनीय काम किया है। ग्रामीण युवाओं को दिशा देकर मृदा परीक्षण, औद्यानिक फसलों में उच्च तकनीकी से जोड़ना एवं दालों का प्रसंस्करण, ग्रेडिंग तथा ट्रेडिंग आदि में युवाओं को आकर्षित किया जाए। उन्हें विभिन्न उत्पादों को बाजार से भी जोड़कर साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता युक्त फूलों की खेती में भी उत्पादन एवं बाजार से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराये जायें। इस तरह की कार्ययोजना पर कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य करें। विभिन्न राज्य सरकारें भी इन युवाओं को प्रचलित कृषि विकास कार्यक्रमों से भी उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं। आज के समय में प्रमुख रूप से गाँवा से शहरों की तरफ युवओं के पलयान की समस्या है। इसे रोकने हेतु राज्य सरकारें अतिरिक्त धन की भी व्यवस्था कर रही हैं। वर्तमान में इस योजना में 80–85 करोड़ रु. व्यय किये जा रहे हैं। अगले 5 वर्षों में इस योजना को 400–500 कृषि विज्ञान केन्द्रों को जोड़े जान का प्राविधान किया जा रहा है।

परियोजना से जुड़े सफलता के मानकों पर आधारित सफलता की कहानियों का भी लेखा–जोखा रखा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र से 5 सफल युवाओं की सफलता की कहानी डाक्यूमेण्ट की जाती है, तो 500 सफल युवा निकलकर आयेंगे। इससे एक बड़ा संदेश

देश में जाएगा और युवा कृषि के प्रति आकर्षित होंगे। जरूरत इस बात की है कि इन युवाओं को कृषि व्यवसायों में जोड़कर स्थायित्व प्रदान करना प्राथमिकता होना चाहिए। यदि कोई कृषि विज्ञान केन्द्र इस कार्य में रुचि नहीं लेता तो ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र को बंद कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में 6 राज्यों के 70 जिलों से प्रवासी मजदूर पलायन किये हैं। इनमें मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों से पलायन किये हैं। इन्हें इन प्रवासी मजदूरों को इनके कौशल आर क्षमता के आधार पर इस परियोजना में जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रवासी मजदूरों में 60 प्रतिशत लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। अतः उन्हें प्रशिक्षित कर विभिन्न व्यवसायों में जोड़ा जाए।

इस अवसर पर उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) डा. ए.के. सिंह ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि अगले 5 सालों में देश के अनेक समस्याओं पर आधारित युवाओं को आर्या परियोजना से जोड़ने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 2015 से 2017 तक 25 कृषि विज्ञान केन्द्र इस परियोजना से आच्छादित थे जिन्हें बढ़ा कर 2018–19 में 96 तथा 2019–20 मं 100 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को आर्या परियोजना से जोड़ा गया है जिस पर 17 करोड़ 61 लाख 17 हजार रुपये की धनराशि व्यय की जा रही है। इस परियोजना में ग्रामीण युवाओं को 4–5 व्यवसायों में नियमित आय प्राप्त कराने की योजना पर काम करना होगा जिसमें विभिन्न संस्थायें अपना योगदान करें। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अब तक 1457 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से 33,324 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें 53.86 प्रतिशत लोगों को विभिन्न व्यवसायों मं जोड़कर नियमित आय प्राप्त कराई जा रही है। ग्रामीण युवाओं/प्रवासी मजदूरों में विशेषकर लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन लोगों को विशेष आर्थिक एवं कौशल आधारित सहयोग देकर सशक्त बनाना कृषि विज्ञान केन्द्रों का दायित्व होना चाहिए। परियोजना के सफल संचालन हेतु बाहरी आर्थिक स्रोतों की भी मदद लेनी चाहिए। भारत सरकार और भा.कृ.अनुप. इस दिशा में विशेष आर्थिक सहयोग कर रहा है। केले के रेशे से अनेकों युवाओं को जोड़ा गया है। यहाँ प्रत्येक युवा 15 से 20 हजार रू. प्रतिमाह की आय प्राप्त कर रहे हैं।

कार्यक्रम में प्रतापगढ़ कृषि विज्ञान केन्द्र ने अपनी परियोजना सम्बंधी प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया। कृषि विज्ञान केन्द्र मुजफ्फरनगर ने अपने केन्द्र की प्रगति एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की कृषि क्षेत्र में आर्या परियोजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने हेतु अति महत्वकांक्षी परियोजना है।

अंत में भा.कृ.अनुप. नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) डा. ए.के. सिंह ने महानिदेशक एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी निदेशकों एवं वैज्ञानिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

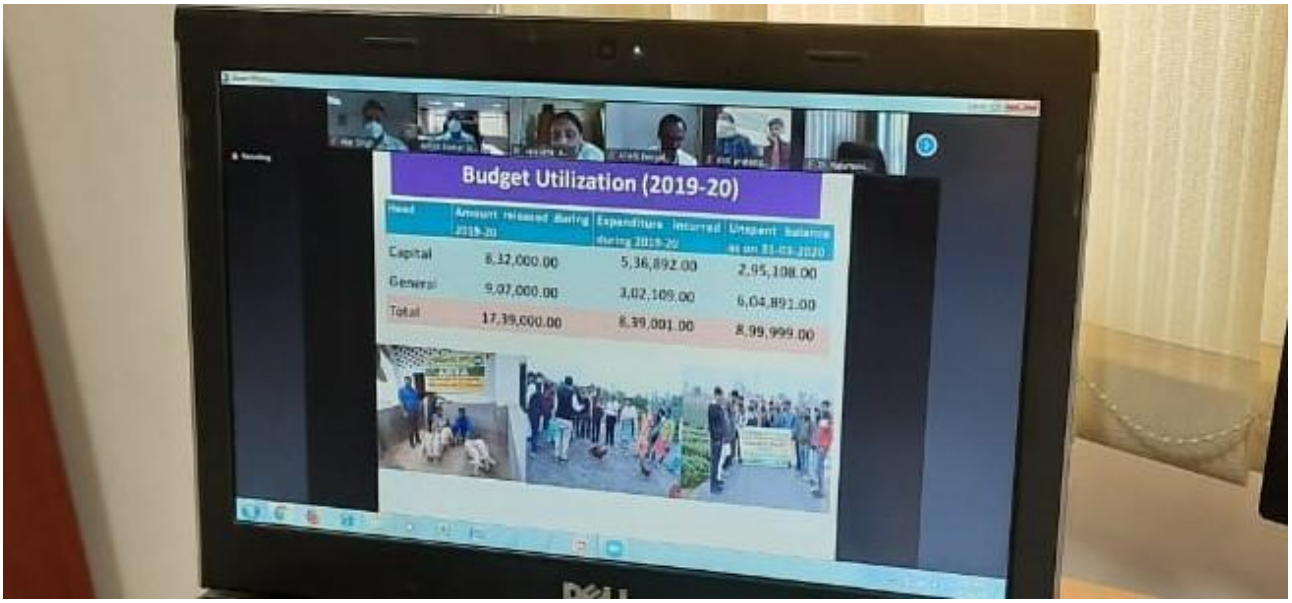
Budget Utilization (2019-20)
Head
Amount released during 2019-20
Expenditure incurred during 2019-20
Unspent balance as on 31-03-2020
Capital
8,32,000.00
5,36,892.00
2,95,108.00
General
9,07,000.00
3,02,109.00
6,04,891.00
Total
17,39,000.00
8,39,001.00
8,99,999.00